IJAER/March-April-2022/Volume-11/Issue-2 ISSN: 2278-9677

International Journal of Arts & Education Research

भारतीय अर्थवस्था में रोजगार के स्तर को बढ़ाने में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका.

भारत भूषण
शोधार्थी
ओ पी जे एस विश्वविद्यालय चूरू राजस्थान

राजेंद्र सिंह
प्रोफेसर
ओ पी जे एस विश्वविद्यालय चूरू राजस्थान

सार

भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र क्षेत्रों के बारे में बात की हैं यह क्षेत्र वर्तमान में भारत में कार्यरत कुल कार्यबल में से 23 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का उदाहरण सभी सेवा क्षेत्र हैं जो आईटी सेवाएं, परामर्श आदि हैं। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र आने वाले वर्षों में देश के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नीतिगत उपायों से विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा । तृतीयक क्षेत्र वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है।

मुख्य शब्द : अर्थव्यवस्था, *तृतीयक क्षेत्र, रोजगार.*

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र हैं, वे हैं; प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और तृतीयक अर्थव्यवस्था। संचालन के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था संगठित और असंगठित में विभाजित है। जबकि स्वामित्व के लिए इसे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। लेकिन आज, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र भी (अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र) को 'सेवा क्षेत्र' (सेवा क्षेत्र) क्यू। अर्थशास्त्र के अन्य क्षेत्र श्प्राथमिक क्षेत्रश (कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि) और श्द्वितीय क्षेत्र (विनिर्वाचन) हैं। तृतीयक क्षेत्र का विकास २०वीं शताब्दी के आरम्भ में शुरू हुआ। व्यापार, यातायात, संप्रेषण (कम्युनिकेशन्स), वित्त, पर्यटन, सत्कार (देखभालता), संस्कृति, मनोरंजक, लोक व्यवस्था और लोक सेवा, सूचना, अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि।

वित्त वर्ष 2021–22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11 प्रतिशत और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4 प्रतिशत रहेगी, जो देश की आजादी के बाद सर्वाधिक है। व्याजपक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में तेजी से हो रही बेहतरी और उपभोग एवं निवेश में त्व रित वृद्धि की संभावनाओं की बदौलत देश में 'ट' आकार में आर्थिक विकास संभव होगा। केन्द्री य वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020–21 पेश की जिसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष के अपेक्षा से कम रहने वाले संबंधित आंकड़ों के साथ–साथ कोविड–19 के उपचार में कारगर टीकों का उपयोग शुरू कर देने से देश में आर्थिक गतिविधियों के निरंतर सामान्यक होने की बदौलत ही आर्थिक विकास फिर से तेज रफ्तार पकड़ पाएगा। देश के बुनियादी आर्थिक तत्वत अब

भी मजबूत हैं क्योंकि लॉकडाउन को क्रमिक रूप से हटाने के साथ–साथ आत्मरनिर्भर भारत मिशन के जरिए दी जा रही आवश्य क सहायता के बल पर अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती के साथ बेहतरी के मार्ग पर अग्रसर हो गई है। इस मार्ग पर अग्रसर होने की बदौलत वर्ष 2019–20 की विकास दर की तुलना में वास्तेविक जीडीपी में 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होगी जिसका मतलब यही है कि अर्थव्य0वस्थास दो वर्षों में ही महामारी पूर्व स्तार पर पहुंचने के साथ–साथ इससे भी आगे निकल जाएगी। ये अनुमान दरअसल आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुरूप ही हैं जिनमें कहा गया है कि भारत की वास्त विक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021–22 में 11.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2022–23 में 6.8 प्रतिशत रहेगी। आईएमएफ के अनुसार भारत अगले दो वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यिवस्थाह बन जाएगा।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 'सौ साल में एक बार' भारी कहर ढाने वाले इस तरह के गंभीर संकट से निपटने के लिए भारत ने अत्यं'त परिपक्वाता दिखाते हुए जो विभिन्न नीतिगत कदम उठाए हैं उससे विभिन्न2 देशों को अनेक महत्वकपूर्ण सबक मिले हैं जिससे वे अदूरदर्शी नीतियां बनाने से बच सकते हैं। इसके साथ ही भारत के ये नीतिगत कदम दीर्घकालिक लाभों पर फोकस करने के महत्वरपूर्ण फायदों को भी दर्शाते हैं। भारत ने नियंत्रण, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों के चार स्तभम्भों। वाली अनूठी रणनीति अपनाई। देश में उभरते आर्थिक परिदृश्य, को ध्यारन में रखते हुए सुव्यकवस्थित ढंग से राजकोषीय और मौद्रिक सहायता दी गई। इसके साथ ही इस दौरान क्रमिक रूप से अनलॉक करते समय संबंधित सरकारी उपायों के राजकोषीय प्रभावों और कर्जों की निरंतरता को भी ध्योन में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान सर्वाधिक असुरक्षित पाए गए लोगों को आवश्यनक सहायता दी गई और इसके साथ ही विभिन्न वस्तुदओं के उपभोग एवं निवेश को काफी बढ़ावा मिला। अनुकूल मौद्रिक नीति से पर्याप्ता तरलता सुनिश्चित हुई। इसी तरह मौद्रिक नीति के कदमों का लाभ प्रदान करते समय कर्जदारों को अस्थोयी मोहलत के जरिए तत्काशल राहत प्रदान की गई।

आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020–21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर (–) 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। प्रथम छमाही में जीडीपी में 15.7 प्रतिशत की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में 0.1 प्रतिशत की अत्यंनत कम गिरावट को देखते हुए ही यह अनुमान लगाया गया है। विभिन्न क्षेत्रों पर नजर डालने पर यही पता चलता है कि कृषि क्षेत्र अब भी आशा की किरण है, जबकि लोगों के आपसी संपर्क वाली सेवाओं, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे जिनमें धीरे–धीरे सुधार देखे जा रहे हैं। सरकारी उपभोग और शुद्ध निर्यात के बल पर ही आर्थिक विकास में और ज्यांदा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है।

विभिन्नर क्षेत्रों में बेहतरी के रुख को ध्यारन में रखते हुए आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि वित्त वर्ष के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में भी उल्लेंखनीय मजबूती देखी गई, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मांग से समग्र आर्थिक गतिविधियों को आवश्यणक सहारा मिला और इसके साथ ही तेजी से बढ़ते डिजिटल लेन–देन के रूप में उपभोग संबंधी ढांचागत बदलाव देखने को मिले। समीक्षा में कहा गया है कि कृषि क्षेत्र की बदौलत वर्ष 2020–21 में भारतीय अर्थव्य वस्था को कोविड–19 महामारी से लगे तेज झटकों के असर काफी कम हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पहली तिमाही के साथ–साथ दूसरी तिमाही में भी 3.4 प्रतिशत रही है। सरकार द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रगतिशील सुधारों ने जीवंत कृषि क्षेत्र

के विकास में उल्लेरखनीय योगदान दिया है जो वित्त वर्ष 2020–21 में भी भारत की विकास गाथा के लिए आशा की किरण है।

वित्त वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पाकदन में 'ट' आकार में बेहतरी देखने को मिली विनिर्माण क्षेत्र ने फिर से तेज रफ्तार पकड़ी। इसी तरह औद्योगिक मूल्यप या उत्पा दन फिर से सामान्यो होने लगा। भारत का सेवा क्षेत्र महामारी के दौरान गिरावट दर्शाने के बाद फिर से बेहतरी के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो गया है। दिसम्बलर में पीएमआई सेवाओं के उत्पाटदन और नए कारोबार में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई।

जोखिम न उठाने की प्रवृत्ति और कर्जों की घटती मांग के कारण वित्त वर्ष 2020–21 में बैंक कर्जों का स्त्र निम्न स्तपर पर बना रहा। हालांकि, कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए दिए गए कर्ज अक्टूकबर 2019 के 7.1 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूतबर 2020 में 7.4 प्रतिशत के स्तधर पर पहुंच गए। अक्टूबर 2020 के दौरान निर्माण, व्यापिार एवं आतिथ्यट जैसे क्षेत्रों में कर्ज प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में बैंक कर्ज का प्रवाह धीमा ही बना रहा। सेवा क्षेत्र को कर्ज प्रवाह अक्टूवबर 2019 के 6.5 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबिर 2020 में 9.5 प्रतिशत हो गया।

उद्देशय

1. भारतीय अर्थवस्था में रोजगार के स्तर पर अध्ययन करना।
2. तृतीयक क्षेत्र पर अध्ययन करना।

खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण ही वर्ष 2020 में महंगाई उच्च2 स्तेर पर बनी रही। हालांकि, दिसम्बबर 2020 में महंगाई दर गिरकर 4+/–2 प्रतिशत की लक्षित रेंज में आकर 4.6 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि नवम्ब र में यह 6.9 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थों विशेषकर सब्जियों, मोटे अनाजों और प्रोटीन युक्तग उत्पामदों की कीमतों में गिरावट होने और पिछले वर्ष के अपेक्षाकृत कम आंकड़ों से ही संभव हो पाया। बाह्य क्षेत्र से भी भारत में विकास को काफी सहारा मिला। दरअसल, चालू खाते में अधिशेष वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान जीडीपी का 3.1 प्रतिशत रहा, जो सेवा निर्यात में उल्लेशखनीय वृद्धि और कम मांग की बदौलत संभव हुआ। इस वजह से निर्यात (वाणिज्यिक निर्यात में 21.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ) की तुलना में आयात (वाणिज्यिक आयात में 39.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ) में तेज गिरावट दर्ज की गई।

इसके परिणामस्व रूप देश में विदेशी मुद्रा भंडार इतना अधिक बढ़ गया जिससे 18 माह के आयात को कवर किया जा सकता है। जीडीपी के अनुपात के रूप में बाह्य या विदेशी ऋण मार्च 2020 के आखिर के 20.6 प्रतिशत से मामूली बढ़कर सितम्बुर 2020 के आखिर में 21.6 प्रतिशत के स्तार पर पहुंच गया। हालांकि, विदेशी मुद्रा भंडार में उल्ले खनीय वृद्धि की बदौलत विदेशी मुद्रा भंडार और कुल एवं अल्पेकालिक ऋण (मूल एवं शेष) का अनुपात बेहतर हो गया।

भारत वित्त वर्ष 2020–21 में भी पसंदीदा निवेश गंतव्यं बना रहा, जो वैश्विक निवेश को शेयरों में लगाने और उभरती अर्थव्यवस्थाकओं में तेजी से बेहतरी आने की संभावनाओं के मद्देनजर संभव हो पाया है। देश में शुद्ध एफपीआई प्रवाह नवम्बवर 2020 में 9.8 अरब डॉलर के सर्वकालिक मासिक

उच्चयतम स्तशर पर पहुंच गया जो निवेशकों में फिर से जोखिम उठाने की प्रवृत्ति बढ़ने, वैश्विक स्तरर पर मौद्रिक नीति को उदार बनाने और घोषित किए गए राजकोषीय प्रोत्सा्हन पैकेजों के मद्देनजर अनुकूल यील्डर हासिल करने पर विशेष जोर देने और अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से संभव हुआ। भारत वर्ष 2020 में विभिन्न् उभरते बाजारों में एकमात्र ऐसा देश रहा जहां इक्विटी में एफआईआई का प्रवाह हुआ। तेजी से ऊंची छलांग लगाते सेंसेक्सआ और निफ्टी की बदौलत भारत ने बाजार पूंजीकरण और सकल घरेलू उत्पासद (जीडीपी) अनुपात अक्टूदबर 2010 के बाद पहली बार 100 प्रतिशत के स्तपर को पार कर गया। हालांकि, इससे वित्तीय बाजारों और वास्ततविक क्षेत्र में कोई सामंजस्ये न होने पर चिंता जताई जाने लगी है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में निर्यात में 5.8 प्रतिशत और आयात में 11.3 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है। भारत में चालू खाते में अधिशेष वित्त वर्ष 2021 में जीडीपी का 2 प्रतिशत रहने की संभावना है जो 17 वर्षों के बाद ऐतिहासिक उच्चतम स्तर है।

तृतीय श्रेणी का उद्योग

यह क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के मामले में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह क्षेत्र सेवा क्षेत्र भी है और जब आप अन्य दो क्षेत्रों के विकास पर विचार करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है। पिछले क्षेत्र की तरह, यह क्षेत्र भी उत्पादों के मूल्य को जोड़ता है। यह क्षेत्र वर्तमान में भारत में कार्यरत कुल कार्यबल में से 23 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देने के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का उदाहरण सभी सेवा क्षेत्र हैं जो आईटी सेवाएं, परामर्श आदि हैं। यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के कुल हिस्से का लगभग 59 प्रतिशत योगदान देता है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या यह है कि जिन नौकरियों में कम वेतन होता है, उनमें ज्यादा रोजगार आकर्षित नहीं होता है। और यह भविष्य की दुविधा बनी हुई है क्योंकि भारत निकट भविष्य में दो अंकों की वृद्धि की तलाश में है।

तृतीयक उद्योग वर्गीकरण

- **दूरसंचार:**

यह एक ऐसा क्षेत्र है जो रेडियो, इंटरनेट और टेलीविजन नेटवर्क पर संकेतों, शब्दों, संकेतों, संदेशों, छवियों, ध्वनियों या किसी भी प्रकार की जानकारी के हस्तांतरण से संबंधित है।

- **पेशेवर सेवाएं:**

तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं जिन्हें कला और विज्ञान में विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सर्जन, वकील और ऑडिटर इस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों में से हैं।

- **फ्रेंचाइजी:**

यह एक निश्चित अवधि के लिए एक विशेष व्यवसाय मॉडल और ब्रांड का उपयोग करने के अधिकार को बेचने का एक अभ्यास है।

तृतीयक क्षेत्र के प्रमुख तथ्य :

1. तृतीयक उद्योग अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र है, जिसमें अन्य बातों के अलावा वित्तीय सेवाएं, चिकित्सा पेशेवर, शिक्षक, नाई और निजी प्रशिक्षक शामिल हैं।

2. तृतीयक क्षेत्र को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैरू लाभ और गैर–लाभकारी।

3. राजस्व सृजन के मामले में, तृतीयक क्षेत्र वर्तमान में विश्व अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है।

4. अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो तृतीयक क्षेत्र का विस्तार होता है जबकि प्राथमिक क्षेत्र, जो कच्चे संसाधन उत्पन्न करता है, गिर जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कुछ योगदान

अप्रैल 2000 और जून 2020 के बीच 83.14 बिलियन अमरीकी डालर की आमद के साथ सेवा क्षेत्र भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। सेवा क्षेत्र की छत्र में कुछ सेवाएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. **अनुसंधान और विकास सेवाएं:** 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, भारत शीर्ष 50 देशों में 48 वें स्थान पर है। प्रतिस्पर्धी लागत पर उपलब्ध उच्च प्रशिक्षित भारतीय जनशक्ति और भारतीय बाजार में उपलब्ध बौद्धिक पूंजी के कारण यह क्षेत्र दुनिया भर में बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। इस कारण से, हाल के वर्षों में, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने अनुसंधान और विकास भाग को भारत में स्थानांतरित कर रही हैं या स्थानांतरित कर रही हैं। यह उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या तो स्थानीय बाजार की सेवा के लिए नए नवीन उत्पादों को विकसित करने में मदद करता है या मूल कंपनी को विश्व बाजारों में उत्पादों को तेजी से वितरित करने में मदद करता है। वर्ष 2022 तक अनुसंधान एवं विकास में भारत का व्यय देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2ः होने का लक्ष्य है।

2. **दूरसंचार सेवाएं:** ट्राई द्वारा थ्ल्20 के अनुसार, भारत में प्रति ग्राहक प्रति माह लगभग 11 जीबी का औसत वायरलेस डेटा उपयोग है जो 2024 तक 18 जीबी तक पहुंचने की उम्मीद है। इस प्रकार, भारत दुनिया भर में डेटा के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है।

3. **आईटी सक्षम सेवाएं** (आईटीईएस)**:** भारत की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और तेजी से बदलते व्यापार के साथ–साथ इंटरनेट के प्रसार के कारण, भारतीय आईटीईएस उद्योग अब दिन–प्रतिदिन अपने क्षेत्र में वृद्धि कर रहा है और एक कठिन प्रतियोगी बन गया है। विश्व बाजार के लिए। सॉफ्टवेयर और आईटी–सक्षम सर्विस्ड निर्यात में भारत की सफलता ने इसे विश्व सेवा निर्यात में हिस्सेदारी के साथ सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक बना दिया है, जो वर्ष 1990 से 2013 तक 0.6ः से बढ़कर 3.3ः हो गया है।

4. **पर्यटन सेवाएं:** ऐतिहासिक विरासत, पारिस्थितिकी में विविधता, भूभाग, समृद्ध संस्कृति और देश भर में फैले प्राकृतिक सौंदर्य के कारण, भारतीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत में महत्वपूर्ण सेवा क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इस प्रकार, पर्यटन हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 2019 के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का कुल योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 6.8: था, और वित्तीय वर्ष 2020 में, भारत में पर्यटन क्षेत्र का देश में कुल रोजगार का 8 प्रतिशत हिस्सा था। उम्मीद है कि 2029 तक भारतीय बाजार में करीब 53 मिलियन नौकरियां सृजित होंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में नीतिगत उपायों से विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में 2019–20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए 2024–25 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विज़न प्रस्तुत किया। इस विज़न का मुख्य आधार है– निवेश प्रेरित विकास और रोजगार सृजन।

इस दिशा में कर नीति उपाय निम्न हैं–

1. स्टार्ट–अप के लिए लाभ से जुड़ी छूट की शुरूआत
2. अवसंरचना जैसे कुछ क्षेत्रों को निवेश से जुड़ी छूट
3. आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन
4. रोजगार सृजन के छूट के लिए दायरे को बढ़ाया गया, योग्यता की शर्तों में ढील दी गई
5. एमएटी देयता की गणना के लिए लाभ दिया जाना और दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत घाटे को आगे ले जाना
6. एमएटी ऋण को आगे ले जाने के लिए समयावधि को 10 साल से बढ़ाकर 15 साल किया गया

घरेलू और विदेश निवेश को बढ़ाने के लिए युक्त पहलों को लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। हमें अवसंरचना, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा लघु और मध्यम कम्पनियों में रोजगार सृजन के लिए भारी निवेश की जरूरत है। मुद्रा ऋण के जरिए आम लोगों के जीवन में बदलाव आया। सरकार ने अपना इरादा जाहिर किया है कि वह ढांचागत संरचना के लिए अगले पांच वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, औद्योगिक गलियारे, समर्पित माल ढुलाई गलियारे, भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं, जलमार्ग विकास एवं उड़ान योजनाओं को लागू किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

अवसंरचना वित्त पोषण के लिए पूंजी के स्रोतों को बढ़ाने हेतु उपाय:

1. ऋण गारंटी विस्तार निगम का गठन 2019–20 के दौरान किया जाएगा।

2. लम्बी अवधि के बॉन्ड के लिए बाजार के विस्तार हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी, इसके लिए विशेष ध्यान अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा।

3. आईडीएफ–एनबीएफसी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई/एफपीआई के निवेश को अनुमति, किसी घरेलू निवेशक द्वारा अधिसूचित लॉक–इन अवधि के अंतर्गत इन्हें हस्तांतरित/बेचा जा सकता है।

4. वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 की तुलना में 2017–18 के दौरान जारी किए गए पेंटेंटों की संख्या में तीन गुनी वृद्धि हुई।

5. अगले दशक के विज़न का उल्लेख बजट में किया गया। इसमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचना के निर्माण, मेक इन इंडिया, एमएसएमई, स्टार्ट–अप, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल, बैटरी, चिकित्सा उपकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसमें विकास और रोजगार सृजन पर फोकस रहेगा।

6. बजट दस्तावेज में नए दशक के विजन का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज में वस्तुगत और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, एमएसएमई, स्र्टाटअप्स पर विशेष रूप से जोर देकर मेक इन इंडिया, रक्षा विनिर्माण, ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रोनिक्स, फैब्स और बैटरियां, चिकित्सा उपकरणों, रोजगार सृजन और विकास पर जोर दिया गया है

7. एमएसएमई के लिए ब्याज छूट योजना के तहत वित्तवर्ष 2019–20 के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को नए या बढ़ते हुए ऋणों पर 2 प्रतिशत ब्याज छूट का प्रावधान है। सरकार एमएसएमई के बिलों का भुगतान करने और सरकारी भुगतानों में देरी को समाप्त करने के लिए उन्हें अपने ही प्लेटफार्म पर भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए एक भुगतान प्लेटफार्म बनाएगी। इसके अलावा सरकार लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को, जिनका वार्षिक व्यापार 1. 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन के लाभ प्रदान करेगी।

बजट में 2019–20 के दौरान 100 नए कलस्टरों की स्थापना की कल्पना की गई है। स्फूर्ति योजना के तहत आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए 50 हजार दस्तकार सक्षम होंगे। इसके अलावा 10 हजार नए किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना का भी प्रस्ताव है ताकि नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता(एस्पायर) योजना के तहत किसानों के लिए पैमाने की अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।मानव संसाधन के सृजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए, बजट में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रस्ताव किया गया है, जो विद्यालय और उच्चतर शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के साथ–साथ बेहतर शासन प्रणाली और अनुसंधान एवं खोज पर और अधिक जोर देगी। इसके अलावा, देश में अनुसंधान के वित्त पोषण, समन्वय और बढ़ावे के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (एनआरएफ) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए, 'विश्व स्तरीय संस्थान' शीर्ष के तहत 400 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना अधिक है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि

पंजीकरण और विवरणी दाखिले के मानकीकरण एवं सुसंगत बनाने के क्रम में अनेक श्रमिक कानूनों को मिलाकर चार श्रमिक कानूनों का एक सेट बनाने का प्रस्ताव, अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर जोर देने के अन्य उपायों में शामिल है।

उपसंहार

भारत में सेवा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार सृजन है। इसलिए इसमें अत्यधिक विकास और अत्यधिक उत्पादक नौकरियां प्रदान करने की क्षमता है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व सृजन होता है। रोजगार सृजन की समस्या को दूर करने के लिए स्किल इंडिया कार्यक्रम का लक्ष्य 2022 तक लगभग 40 करोड़ लोगों को बाजार से संबंधित कौशल प्रदान करना है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को अपनाकर और उन्हें प्रदान करके ऐसा करना है। आवश्यक धन के साथ। इसी तरह, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना है और इस प्रकार, सेवा क्षेत्र के पोर्टफोलियो को जोड़ने में एक गुणक प्रभाव पैदा करेगा। इन परिस्थितियों में, स्टार्टअप इंडिया पहल भारत में विनिर्माण और साथ ही सेवा उद्योग दोनों के लिए अभिनव स्टार्टअप का समर्थन करने की पेशकश करके एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है।

संदर्भ सूचि :

[1]. मुखर्जी ए, "भारत में सेवा क्षेत्ररू रुझान, मुद्दे और आगे के तरीके"। 2012.
[2]. दत्त। और ए. महाजन, भारतीय अर्थव्यवस्था, पृष्ठ–81।
[3]. बी. आइचेंग्रीन, पूनम गुप्ता, ष्भारत के आर्थिक विकास के मार्ग के रूप में सेवा क्षेत्रष्। फरवरी 2011।
[4]. अर्पिता मुखर्जी, "भारत में सेवा क्षेत्र," जून 2013.
[5]. आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16: सेवा क्षेत्र 2015–16, 26 फरवरी–2016 में 66.1ः योगदान करने वाले आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है
[6]. ढींगरा, ईश्वर सी. (2005); भारतीय अर्थव्यवस्थारू पर्यावरण और नीति; सुलतान
[7]. चंद एंड संस; नई दिल्ली।
[8]. दीक्षित, ए.के. (1996); द मेकिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, द एमआईटी प्रेस।
[9]. ग्वार्टनी, जेम्स डी. और स्ट्रूप; रिचर्ड, एल। (1992); अर्थशास्त्ररू निजी और सार्वजनिक पसंद, छठा संस्करण।
[10]. दत्त, रूद्र एवं के.पी.एम. सुन्दरम (2010), भारतीय अर्थ व्यवस्था, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली।
[11]. लाल एस.एन. एवं एस.के. लाल (2010) भारतीय अर्थ व्यवस्था – सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, शिवम् पब्लिशर्स, इलाहाबाद।